3. राष्ट्रीय / अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

4. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम

5. निष्पादन पुरस्कारों के लिए स्कीम।

6. खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हेतु स्कीम

7. आर्थिक व मानीटरिंग सेल की स्थापना समेत प्लान पोस्ट हेतु स्कीम।

जबलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-7 की मरम्मत

2384. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 पर रद्दी चौकी से धमापुर चौक तक की सड़क पाइप लाइन के रिसने से बहुत खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो पाइप लाइन को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उस स्थान से पाइप लाइन को कब तक हटाया जाएगा; और

(घ) सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग का कथित भाग एक "अनुपयुक्त शहरी संपर्क मार्ग" का हिस्सा है जिसके विकास और रख-रखाव का कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को रिसाव को बन्द करने और पाइपलाइन को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।

Permission to Paper Pulp Company, Pune, Maharashtra

2385. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any paper and pulp company situated at Indapur District Pune, Maharashtra has been granted permission by Central Government;

(b) whether the clearance was suspended on the 6th June, 1995 because of the perenial water problem faced in the area;

(c) whether the evaluation committee visited the site on 4th September, 1995 if so, what are the findings of the evaluation committee; and

(d) whether the suspension stands revoked; and if so, on what date with details thereof.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Yes, Sir. The project was accorded clearance from the environmental angle subject to certain environmental safeguards on 27th April, 95 but such clearance was suspended on 16th June, 95.

(c) The site visit team observed that no significant deterioration on the quality of back waters of Ujanni Dam or on the availability of the water in the region are envisaged as the project is based on imported bleached pulp.

(d) Yes, Sir. The suspension order was withdrawn on 25th July, 95 subject to the condition that the Ministry reserves the right to cancel the environmental approvaloif, after the site visit, the project is not found environmentally compatible.

Mangalore Refinery Project

2386. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what are the details of development of Mangalore Refinery project so far;

(b) by when the project is likely to be completed; and

(c) what is the estimated cost of the project?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) In April 1991, Government had approved the setting up

of a 3 MMTPA capacity grass-root refinery at Mangalore as a Joint Venture, between HPCl and Indian Rayon Industries Limited. The implementation of the Mangalore Refinery project is in progress and actual physical progress as on September, 1995 was about 90%.

(b) The project is expected to be completed by June, 1996.

(c) The revised estimated cost is about Rs. 2593 crores, including FE component of Rs. 944.20 crores.

'Plundering of Money by Van Vibhag in U.P.'

2387. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Van Vibhag in all the districts in U.P. are involved in plundering money and are doing little towards environment and forests; and

(b) if so, the steps being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The information is being sought from the State Government of UP and will be laid on the Table of the House.

Payment of Environmental Rent

2388. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether India has demanded that Western countries should pay "environmental rent" for the excessive emission of Green House cases;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Western countries on this demand?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The argument pertaining to 'environment rent' has been advanced by India in the nature of stressing the point that the developed nations have excessively utilised the common resource of atmosphere in the past and continue to do so. The estimates of the 'environmental rent' worked out by Indian researchers are of the order of US dollars 70 billion equivalent per year.

(c) Western countries have not formally made known their reaction.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधायें उपलब्ध करना

2389. **श्री अजीत जोगी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में गाद का भरना

2390. **श्री नरेश बाबल:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न पत्तनों में समुद्र तल में भर रही गाद को निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रयोजनार्थ कोई तंत्र है; और

(ग) यदि नहीं तो भारत सरकार ने किन-किन देशों को इस कार्य के संबंध में ठेका दिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में विभिन्न पत्तनों की निकर्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, भारतीय निकर्षण निगम (डी० सी० आई) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, कुछेक महापत्तनों को उनके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र से गाद निकालने के लिए निकर्षण उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं।